पंजाब राज्य और अन्य

बनाम

द सीनियर वोकेशनल स्टाफ मास्टर एसोसिएशन और अन्य

(सिविल अपील संख्या 632/2008)

18 अगस्त, 2017

[दीपक मिश्रा, आर. के. अग्रवाल और प्रफुल्ल सी. पंत, जे. जे.]

सेवा कानूनः पदों की समानता-व्यावसायिक परास्नातक का पद-प्रारंभ में शैक्षणिक योग्यता या तो इंजीनियरिंग में डिग्री या बी. ए. आई. टी. आई. डिप्लोमा के साथ थी-उनका वेतनमान व्याख्याताओं की तुलना में अधिक था-वर्ष 1978 में व्यावसायिक परास्नातक और व्याख्याताओं को एक ही पैमाने पर रखा गया था-अधिसूचना दिनांक 31.3.1995 द्वारा स्नातक व्यावसायिक परास्नातक और स्नातकोत्तर व्यावसायिक परास्नातक को फिर से नामित किया गया था, लेकिन व्यावसायिक व्याख्याताओं को फिर से नामित किया गया था। जिम्मेदारियाँ और वित्तीय निहितार्थ प्रभावित नहीं हुए-अधिसूचना दिनांक 31.3.1995 को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी-याचिका के लंबित रहने के दौरान, सेवा नियमों में संशोधन किया गया था-इसके द्वारा व्याख्याताओं के वेतनमान को व्यावसायिक स्नातकोत्तरों की तुलना में अधिक कर दिया गया था-व्यावसायिक स्नातकोत्तरों ने राज्य सरकार से संपर्क किया और दावा किया कि वेतनमान व्याख्याताओं के बराबर है-राज्य सरकार ने 7.11.2002 और 16.5.2003 की अधिसूचनाओं द्वारा केवल उन लोगों को उच्च वेतनमान का लाभ दिया, जो 8.7.1995 से पहले सेवा में थे-राज्य सरकार ने अधिसूचना दिनांक 16.7.2003 ने दिनांकित 7.11.2002 और 16.5.2003 अधिसूचनाओं को यह स्पष्ट करते हुए रद्द कर दिया कि केवल वे व्यावसायिक परास्नातक जिन्हें 8 से पहले नियुक्त किया गया था।

और जिन्होंने 8.7.1995 द्वारा इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर और या डिग्री की योग्यता प्राप्त की है, वे उच्च वेतनमान के लिए पात्र होंगे-व्यावसायिक परास्नातक ने 16.07.2003 की अधिसूचना को चुनौती दी।16.7. 2003-उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने दिनांक 1 की अधिसूचना को रद्द कर दिया और राज्य सरकार को दिनांक 2 की अधिसूचना का लाभ देने का निर्देश दिया-उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने एल. पी. ए. को खारिज कर दिया-अपील पर अभिनिर्धारित कियाः शुरुआत से ही, व्यावसायिक परास्नातक के रूप में नियुक्ति के लिए शैक्षिक योग्यता एक डिग्री या डिप्लोमा रही है क्योंकि दोनों योग्यताओं को बराबर रखा गया था। सभी को चयन की एक सामान्य प्रक्रिया द्वारा नियुक्त किया गया था और सभी एक ही काम कर रहे थे। .यह केवल "बाद में ही हुआ कि राज्य सरकार ने कुछ व्यावसायिक परास्नातकों को व्यावसायिक व्याख्याताओं के रूप में नामित किया और दोनों के बीच एक कृत्रिम अंतर लाया-पुनः पदनाम के बाद भी, व्यावसायिक व्याख्याताओं की जिम्मेदारियों और वित्तीय मामलों में कोई बदलाव नहीं हुआ-व्यावसायिक व्याख्याताओं और व्यावसायिक परास्नातकों के बीच कोई अंतर नहीं हैः - व्यावसायिक परास्नातकों के वेतन और भत्तों में कटौती करने का कोई भी प्रयास मनमानेपन के बराबर होगा, यदि इसके लिए कोई उचित औचित्य नहीं दिया जाता है-इसलिए, उच्च न्यायालय को यह कहते हुए उचित ठहराया गया कि व्यावसायिक परास्नातक उच्च वेतनमान के हकदार थे-अधिसूचना दिनांक 16.7.2003 प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन के आधार पर भी रद्द किया जा सकता है क्योंकि इसे संबंधित कर्मचारियों-भारत का संविधान-कला को सुने बिना पारित किया गया था। 14-पंजाब राज्य शिक्षा कक्षा III (स्कूल संवर्ग) सेवा नियम, 1978।

भारत का संविधानः अनुच्छेद, 14 से 18-समानता की प्रकृति और कार्यक्षेत्रः समानता का सिद्धांत एक गतिशील और विकसित अवधारणा है जिसके कई आयाम हैं-कला। 14 वर्ग विधान को मना करता है, लेकिन उचित वर्गीकरण को मना नहीं करता

है-वर्गीकरण बोधगम्य भेद पर आधारित होना चाहिए और भेद का नियम या विचाराधीन वैधानिक प्रावधान द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ एक उचित संबंध होना चाहिए-राज्य द्वारा किसी भी नीति के निर्माण में समानता का सिद्धांत भी मौलिक है जो संविधान के अनुच्छेद 38,39,39ए, 43 और 46 से स्पष्ट है-यदि राज्य एक वर्ग को कुछ आर्थिक लाभ दे रहा है जबकि दूसरे को इससे इनकार कर रहा है, तो एक ही झूठ को उचित ठहराने की जिम्मेदारी राज्य पर है, विशेष रूप से जब दोनों वर्गों के साथ अतीत में राज्य द्वारा समान व्यवहार किया गया था।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने अभिनिर्धारित किया-

1.1 यह कानून का एक प्रमुख सिद्धांत है कि सरकार को कानून के शासन का पालन करना होगा और भारत के संविधान के मूल्यों और सिद्धांतों को बनाए रखना होगा। समानता का सिद्धांत एक गतिशील और विकसित अवधारणा है जिसके कई आयाम हैं। संविधान के अनुच्छेद (आई. डी. 1), कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण का आश्वासन देने के अलावा, रोजगार के मामलों में समानता प्राप्त करने के उद्देश्य वाले भेदभाव को भी अस्वीकार करते हैं।

यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि हालांकि अनुच्छेद 14 वर्ग कानून को मना करता है लेकिन यह उचित वर्गीकरण को मना नहीं करता है। जब वर्गीकरण प्रदान करने वाले सांविधिक प्रावधान के किसी भी नियम पर इस आधार पर हमला किया जाता है कि यह अनुच्छेद 14 के विपरीत है, तो इसकी वैधता को बनाए रखा जा सकता है यदि यह दो परीक्षणों को संतुष्ट करता है, अर्थात्, वर्गीकरण एक बोधगम्य अंतर पर आधारित होना था जो व्यक्तियों या चीजों को समूह से बाहर रखे गए अन्य लोगों से अलग करता है, और विचाराधीन अंतर में नियम या विचाराधीन वैधानिक प्रावधान द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के लिए एक उचित संबंध होना चाहिए। दूसरे शब्दों में,

वर्गीकरण के आधार और क़ानून या नियम द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के बीच कुछ तर्कसंगत संबंध होना चाहिए। [पैरा 14] [666-डी-जी)

1.2 समानता का सिद्धांत, राज्य द्वारा किसी भी नीति के निर्माण में भी मौलिक है और इसकी झलक संविधान के भाग IV में सन्निहित अनुच्छेद 38,39,39ए, 43 और 46 में पाई जा सकती है। संविधान के इन अनुच्छेदों में कहा गया है कि राज्य एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए संवैधानिक दायित्व के अधीन है जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करे, अन्य बातों के साथ-साथ, मौद्रिक असमानताओं को कम करे, और आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार सुनिश्चित करे और पर्याप्त मजदूरी प्रदान करे ताकि जीवन का एक उचित स्तर सुनिश्चित किया जा सके और कमजोर वर्गों के आर्थिक हितों को बढ़ावा दिया जा सके। अर्थात्, यदि राज्य एक वर्ग को कुछ आर्थिक लाभ दे रहा है, जबकि दूसरे को इससे वंचित कर रहा है, तो इसे उचित ठहराने की जिम्मेदारी राज्य पर है, विशेष रूप से उन परिस्थितियों में जब दोनों वर्गों या व्यक्तियों के समूह के साथ राज्य द्वारा अतीत में समान व्यवहार किया गया था। समान रूप से स्थित व्यक्तियों के बीच कोई भेदभाव नहीं हो सकता है, चाहे वह सरकारी अधिसूचना के माध्यम से हो या नियमों में किसी संशोधन के माध्यम से। [पारस 16 और 17) [667-एफ, एच; 668-ए-बीजे

1.3 वर्तमान मामले में, शुरुआत से ही, व्यावसायिक परास्नातक के रूप में नियुक्ति के लिए शैक्षिक योग्यता तीन साल के अनुभव के साथ एक डिग्री या डिप्लोमा थी क्योंकि दोनों योग्यताओं को बराबर रखा गया था। सभी व्यक्तियों को चयन की एक सामान्य प्रक्रिया द्वारा नियुक्त किया गया था और वे एक ही काम करते हुए एक ही वर्ग को पढ़ाते हैं। इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों के बीच कोई भेद नहीं किया जा सकता है। इसके बाद ही अपीलकर्ताओं ने कुछ व्यावसायिक परास्नातकों को व्यावसायिक व्याख्याताओं के रूप में नामित किया और दोनों के बीच एक कृत्रिम अंतर लाया। यहां

तक कि व्यावसायिक व्याख्याताओं के रूप में डिग्री धारकों और स्नातकोत्तरों के पुनर्विन्यास के कारण, कथित अधिसूचना से पहले डिग्री धारकों और डिप्लोमा धारकों के बीच जिम्मेदारियों और वित्तीय मामलों में कोई बदलाव नहीं हुआ था, जो तथ्य राज्य द्वारा विधिवत स्वीकार किया जाता है। व्यावसायिक व्याख्याताओं और व्यावसायिक परास्नातकों के बीच कोई अंतर नहीं है और वे एक एकीकृत संवर्ग और वर्ग बनाते हैं। (पैरा 161 (667-सी-एल)

1.4 जहां तक काम की प्रकृति का संबंध है, यह कहा गया है कि व्यावसायिक परास्नातक इंजीनियरिंग/गैर-इंजीनियरिंग ट्रेडों में वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं और उनके पास तकनीकी योग्यता है, जबकि व्यावसायिक व्याख्याता भी उन्हीं स्कूलों में समान कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। व्यावसायिक परास्नातक और व्याख्याता दोनों एक ही कक्षाओं में पढ़ा रहे हैं और इसलिए काम, जिम्मेदारियों और कर्तव्यों की प्रकृति समान है और 1978 से वेतनमान भी समान रखे गए थे। (पैरा 16) (667-एफ-जी)

1.5 चूँकि व्यावसायिक परास्नातक 4 'वेतन आयोग के आवेदन से पहले व्यावसायिक व्याख्याताओं के समान वेतन प्राप्त कर रहे थे, इसलिए उनके वेतन और भत्तों में कटौती करने का कोई भी प्रयास मनमानेपन के बराबर होगा जिसे कानून की नजर में बनाए नहीं रखा जा सकता है यदि इसके लिए कोई उचित औचित्य नहीं दिया जाता है। [पैरा 17) [668-सी]

1.6 शैक्षणिक योग्यता और कर्तव्यों की प्रकृति के आधार पर एक अंतर पैमाने की अनुमति है; हालाँकि, यह समान रूप से स्पष्ट है कि यदि दो श्रेणियों के कर्मचारियों को शुरू में समान माना जाता है, तो उनके साथ ऐसा व्यवहार तब तक जारी रहना चाहिए जब तक कि कुछ ठोस कारणों से एक अलग व्यवहार को उचित नहीं ठहराया

जाता है। ऐसे मामले में जहां कर्तव्यों की प्रकृति में भारी बदलाव किया जाता है, वेतन के अंतर पैमाने को उचित ठहराया जा सकता है। इसी तरह, यदि किसी विशेष पद के लिए उच्च योग्यता निर्धारित की जाती है, तो उच्च वेतनमान दिया जा सकता है। हालाँकि, यदि बुनियादी योग्यताएँ और नौकरी की आवश्यकताएँ वही बनी रहती हैं जो वे शुरू में निर्धारित की गई थीं, तो न्यायालय एक अंतर व्यवहार के अनुसार प्राधिकरण की कार्रवाई को स्वीकार करने में अनिच्छुक होगा जब तक कि कुछ अच्छे कारणों का खुलासा नहीं किया जाता है। (पैरा 18) (668-डी-एफ)

1.7 उच्च न्यायालय ने यह घोषणा करते हुए पूरी तरह से न्यायसंगत ठहराया कि व्यावसायिक स्वामी इस आधार पर रु. 1,640/- के वेतनमान के हकदार हैं कि व्यावसायिक आचार्यों द्वारा किए जा रहे कर्तव्यों की प्रकृति व्यावसायिक व्याख्याताओं के समान है और दोनों के बीच वर्गीकरण करने के पीछे कोई तर्क नहीं था, विशेष रूप से जब दोनों श्रेणियों को वार्डों पर 1978 से सभी पिछले वेतन संशोधनों में एक और समान माना जाता था। दिनांक 1 की अधिसूचना के अनुसार, केवल व्यावसायिक परास्नातकों के नामों को उनके कर्तव्यों और वेतनमान की प्रकृति को बदले बिना बदल दिया गया था। [पैरा 19] [668-जी-एच)

वी. मार्कंडेय और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य (1989) 3 एस. सी. सी. 191: [19891 2 एस. सी. आर. 422; उत्तर प्रदेश राज्य। और अन्य बनाम जे. पी. चौरसिया और अन्य (1989) 1 एस. सी. सी. 121: [1988) 3 सप्ट; "एस. सी. आर. 288; श्याम बाबू वर्मा और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (1994) 2 एस. सी. सी. 521: [19941 1 एस. सी. आर. 700; डब्ल्यू. बी. सरकार। बनाम तरुण के. रॉय और अन्य (2004) 1 एस. सी. सी. 347: [20031 5 पूरक। एससीआर 656; इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड बनाम वर्कमेन, इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (2007) 1 एससीसी 408: [20061 9 सप्लीमेंट। एस. सी. आर. 73; भारतीय

स्टेट बैंक और अन्य बनाम के. पी. सुब्बैया और अन्य (2003) 11 एस. सी. सी. 646: [20031 1 पूरक। एससीआर 545-प्रतिष्ठित।

2. इसके अलावा, दिनांकित 16.07.2003 का विवादित आदेश इस आधार पर रद्द किया जाना चाहिए कि इसे प्राकृतिक न्याय के नियमों का पालन किए बिना पारित किया गया है। संबंधित कर्मचारियों को सुनवाई का अवसर दिए बिना इसे पारित नहीं किया जा सकता था। उत्तरदाताओं को बिना सुने भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा था। कार्रवाई में निष्पक्षता इस बात की गारंटी देती है कि ऐसा कोई भी आदेश जो किसी कर्मचारी को नागरिक परिणामों से पीड़ित करता है, संबंधित को नोटिस दिए बिना और मामले में उसे सुनवाई दिए बिना पारित नहीं किया जाना चाहिए। [पारस 19 और 21) [669-ए, एच; 670-एजे

भगवान शुक्ला बनाम भारत संघ और अन्य। ए. आई. आर. 1994 एस. सी. 2480: [19941 2 पूरक। एस. सी. आर. 419-निर्भर

सिविल अपील क्षेत्राधिकार: 2008 की सिविल अपील सं. 632 .

एल. पी. ए. Nos. 66 और 2006 के 67 (0 और एम) में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 23.05.2006 से।

अपीलार्थियों के लिए अधिवक्ता करण भरीहोक, सुश्री अनुषा नागराजन, अजय पाल।

निधेश गुप्ता, नीरज के. जैन, वरिष्ठ अधिवक्ता तनम गुप्ता, पुनीत वार्ष्णेय, सुश्री वृति गुजराल, वरिंदर कुमार शर्मा, सुश्री पारुल शर्मा, आदित्य कुमार चौधरी, अखिल आनंद, सुश्री वैशाली दीक्षित, अशोक के. महाजन, उत्तरदाताओं के वकील।

न्यायालय का निर्णय आर. के. अग्रवाल, जे. द्वारा दिया गया-

उपरोक्त अपील पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा चंडीगढ़ में 2006 के एल. पी. ए. संख्या 66 में सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 2003 के सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 10928 और सी. डब्ल्यू. पी. एन. संख्या 2006 के एल. पी. ए. संख्या 67 में पारित किए गए विवादित सामान्य निर्णय और आदेश के खिलाफ दायर की गई है। 1995 का 7527 जिसके द्वारा खंड पीठ ने अपीलार्थियों द्वारा दायर अपीलों को खारिज करते हुए 2003 के सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 10928 और 1995 के 7527 में उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 1 के आदेश को बरकरार रखा।

2. संक्षेप तथ्यः-

(a) सीनियर वोकेशनल स्टाफ मास्टर्स एसोसिएशन-प्रतिवादी एसोसिएशन पंजाब राज्य में 1975,1982,1983 और उसके बाद के वर्षों के दौरान नियुक्त किए गए वोकेशनल मास्टर का प्रतिनिधित्व करता है। उत्तरदाताओं को वर्ष 1975 में पंजाब राज्य द्वारा तदर्थ आधार पर उनके संबंधित पदों पर नियुक्त किया गया था। वर्ष 1978 में, पंजाब लोक सेवा आयोग ने नियमित नियुक्ति के माध्यम से व्यावसायिक परास्नातक के 132 पदों को भरने के लिए विज्ञापन दिया। इन पदों को पंजाब स्कूल शिक्षा (पी. एस. ई.) कक्षा तीन (स्कूल संवर्ग) नियमों के तहत भरा जाना था। व्यावसायिक परास्नातक के पदों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता डिग्री या स्नातकोत्तर थी, सिवाय उन बहुत कम पाठ्यक्रमों के जहां विज्ञापन के तहत शैक्षिक योग्यता डिप्लोमा थी।

(b) वर्ष 1992-93 में, राज्य सरकार ने व्यावसायिक मास्टर के रूप में नियुक्त होने के लिए न्यूनतम योग्यता को संशोधित करने का निर्णय लिया और कुछ पाठ्यक्रमों के लिए डिग्री के स्थान पर न्यूनतम शैक्षिक योग्यता के रूप में डिप्लोमा प्रदान किया गया। संशोधन के कारण, दो वर्ग थे। राज्य में व्यावसायिक परास्नातक, अर्थात डिप्लोमा धारक व्यावसायिक परास्नातक और डिग्री धारक व्यावसायिक

परास्नातक या स्नातकोत्तर व्यावसायिक परास्नातक। राज्य सरकार ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि योग्यता में संशोधन के कारण असमान लोगों को समान माना जा रहा है, अधिसूचना दिनांक 31/03/1995 के अनुसार, डिग्री धारक व्यावसायिक मास्टर और स्नातकोत्तर व्यावसायिक मास्टर को व्यावसायिक व्याख्याता के रूप में फिर से नामित किया गया है, इस शर्त के साथ कि उनकी वर्तमान जिम्मेदारियों और वित्तीय मामलों में कोई बदलाव नहीं होगा। यहां यह भी उल्लेख करना उचित है कि डिप्लोमा धारक व्यावसायिक परास्नातकों को डिग्री या स्नातकोत्तर योग्यता प्राप्त करने पर व्यावसायिक व्याख्याताओं के रूप में फिर से नामित करने का अवसर भी प्रदान किया गया था।

(c) पंजाब राज्य में सभी व्यावसायिक परास्नातकों को व्यावसायिक व्याख्याताओं का पदनाम देने के लिए अपीलकर्ताओं को निर्देश देने के लिए शेष व्यावसायिक परास्नातकों द्वारा 1995 की सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 7527 में उच्च न्यायालय के समक्ष उक्त अधिसूचना दिनांकित 31/03/1995 को चुनौती दी गई थी। उक्त रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, राज्य सरकार ने पंजाब राज्य शिक्षा वर्ग (स्कूल संवर्ग) सेवा नियम, 1978 में संशोधन करने के लिए नियम बनाए, जिसमें व्यावसायिक मास्टर और व्यावसायिक व्याख्याताओं के लिए अलग योग्यता निर्धारित की गई थी।

(d) चौथे पंजाब वेतन आयोग की शुरुआत पर आयोग ने व्यावसायिक परास्नातकों को सामान्य अध्ययन के परास्नातकों और व्यावसायिक व्याख्याताओं को सामान्य अध्ययन के व्याख्याताओं से अलग नहीं माना था और व्यावसायिक परास्नातकों को स्कूल के परास्नातकों और व्यावसायिक व्याख्याताओं के साथ स्कूल के व्याख्याताओं के साथ विलय कर दिया था। 6, 400-10,640/- और स्कूल मास्टर्स को

रु। 5,800-- 9, 200/-। यहां यह उल्लेख करना उचित है कि पहले व्यावसायिक परास्नातक और व्यावसायिक व्याख्याताओं को समान वेतनमान दिया जाता था.

(e) इसमें उत्तरदाताओं ने 4 'वेतन आयोग द्वारा दिए गए वेतनमान में असमानता से व्यथित होकर राज्य सरकार से संपर्क किया और दावा किया कि उन्हें व्याख्याताओं के समान वेतनमान दिया जाना चाहिए। पंजाब सरकार के शिक्षा विभाग ने दिनांक 07.11.2002 की अधिसूचना के माध्यम से स्पष्ट किया कि "08.07.1995 पर या उसके बाद नियुक्त व्यावसायिक परास्नातकों को न तो शैक्षिक योग्यता के आधार पर व्यावसायिक व्याख्याता के रूप में नामित किया जा सकता है और न ही रु। रुपये के स्थान पर 6,400-10,640/-। 5,800-9,200/- उन्हें 01.01.1996 से प्रदान किया जाए। दूसरे शब्दों में, उच्च स्तर का लाभ उन लोगों के लिए स्वीकार्य होगा जो 08.07.1995 से पहले सेवा में थे "16.05.2003 की एक बाद की अधिसूचना के माध्यम से, राज्य सरकार ने दिनांकित 07.11.2002 अधिसूचना में लिए गए रुख को दोहराया और इसका सख्ती से पालन करने की भी मांग की।

(f) पंजाब सरकार के शिक्षा विभाग ने दिनांक 16.07.2003 की अधिसूचना के माध्यम से, इस स्थिति को स्पष्ट करते हुए 07.11.2002 और 16.05.2003 की अधिसूचनाओं को रद्द कर दिया कि केवल वे व्यावसायिक परास्नातक जो 08.07.1995 से पहले नियुक्त किए गए थे और जिन्होंने 08.07.1995 द्वारा इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर या डिग्री की योग्यता प्राप्त की थी, वे रुपये के वेतनमान के लिए पात्र होंगे। 01.01.1996 से प्रभावी 6,400-10,640/- और पहले की अधिसूचनाओं के आधार पर किसी भी अयोग्य व्यावसायिक मास्टर को दी जा रही अतिरिक्त राशि की वसूली के लिए एक निर्देश भी जारी किया।

(g) दिनांकित 16.07.2003 अधिसूचना से व्यथित होने के कारण, उत्तरदाताओं ने उच्च न्यायालय के समक्ष 2003 की सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 10928 को प्राथमिकता दी। उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने 2003 के सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 10928 और 1995 के 7527 में दिनांकित एक सामान्य निर्णय और आदेश के माध्यम से, दिनांकित 16.07.2003 अधिसूचना को रद्द कर दिया और राज्य सरकार को 08.07.1995 से पहले भर्ती किए गए सभी व्यावसायिक परास्नातकों को दिनांकित 31.03.। 995 की अधिसूचना का लाभ देने का निर्देश दिया।

(h) दिनांक 1 के आदेश से व्यथित राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के समक्ष 2003 के सी. डब्ल्यू. पी. सं. 10928 में 2006 की एल. पी. ए. सं. 66 और 1995 के सी. डब्ल्यू. पी. सं. 7527 में 2006 की एल. पी. ए. सं. 67 को प्राथमिकता दी। उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने सामान्य निर्णय और दिनांक 23.05.2006 के आदेश के माध्यम से अपीलार्थियों द्वारा दायर अपीलों को खारिज कर दिया।

(।) 23, 05.2006 के आदेश से व्यथित होकर, अपीलकर्ताओं ने विशेष अनुमति के माध्यम से इस अपील को प्राथमिकता दी है।

3. अपीलार्थियों के विद्वान वकील श्री करण भरीहोके और संबंधित प्रत्यर्थियों के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री नीरज कुमार जैन और श्री निधेश गुप्ता द्वारा प्रस्तुत दलीलों को सुना और अभिलेखों का अध्ययन किया।

विचार के लिए बिंदुः-

4. इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए एकमात्र बिंदु यह है कि क्या मामले के वर्तमान तथ्यों और परिस्थितियों में, 16.07.2003 की अधिसूचना कानून की नजर में मान्य है या नहीं?

प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियाँः

5. अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने इस न्यायालय के समक्ष तर्क दिया कि उत्तरदाता व्याख्याता की मूल योग्यता को पूरा नहीं करते हैं। यह आगे तर्क दिया गया कि उच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर विचार नहीं किया है कि प्रतिवादी दिनांकित अधिसूचना को चुनौती नहीं दे सकते थे क्योंकि उक्त अधिसूचना को दिनांकित सांविधिक नियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने इस तथ्य का एक गलत निष्कर्ष दर्ज किया है कि अधिसूचना दिनांक 1 प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है और उत्तरदाताओं को वेतन और भत्ते के रूप में भुगतान की गई अतिरिक्त राशि की वसूली का कोई सवाल ही नहीं है। विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया कि यह कानून का एक अच्छी तरह से स्थापित प्रस्ताव है कि कर्मचारियों के एक वर्ग के वेतनमान का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा राज्य की योग्यताओं, जिम्मेदारियों, काम की प्रकृति और संसाधनों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है और उच्च न्यायालय को रुपये का वेतनमान नहीं देना चाहिए था। 6,400-10,640/- यहाँ उत्तरदाताओं के लिए-व्यावसायिक कर्मचारी परास्नातक। विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया कि पहले की गई त्रुटि को सुधारने के लिए, राज्य सरकार द्वारा रुपये के वेतनमान को वापस लेने के लिए अधिसूचना दिनांक 16.07.2003 जारी की गई थी। 6,400-10,640/- व्यावसायिक मास्टर्स को डब्ल्यू. ई. एफ. 01.01.1996 जिसे अनजाने में अधिसूचना दिनांक 07.11.2002 के माध्यम से दिया गया था, और उत्तरदाताओं के किसी भी वैध अधिकार में बाधा डालने के लिए राज्य की ओर से कोई गड़बड़ी नहीं है क्योंकि यह राज्य का विशेषाधिकार है। विद्वान वकील ने अंत में तर्क दिया कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश गलत हैं और वैधानिक नियमों का घोर उल्लंघन है और इस न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया जाना चाहिए। अपनी दलीलों के समर्थन में, विद्वान वकील ने इस न्यायालय के निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा किया है जो इस प्रकार हैंः -

(i) वी. मार्कंडेय और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य (1989) 3 एस. सी. सी. 191 में, यह निम्नानुसार आयोजित किया गया थाः -

> "10. रणधीर सिंह मामले में और बाद में धीरेंद्र चमोली मामले में, सुरिंदर सिंह मामले में, भगवान दास मामले में, जयपाल मामले में और पी. सविता मामले में, इस अदालत ने "समान काम के लिए समान वेतन" के सिद्धांत को लागू किया। अदालत ने एक ही नियोक्ता के तहत दो वर्गों के कर्मचारियों द्वारा किए गए समान या समान काम के आधार पर समान वेतन के सिद्धांत पर राहत दी, भले ही दोनों वर्गों के कर्मचारी एक ही सेवा का गठन नहीं करते थे। लेकिन उपरोक्त सभी मामलों में राहत तभी दी गई जब यह पाया गया कि संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 में निहित खंड में समानता का उल्लंघन करते हुए विभिन्न वेतनमान देने में भेदभाव किया गया था। समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत को इस आधार पर लागू किया गया था कि बिना किसी तर्कसंगत वर्गीकरण के समान कर्तव्यों और कार्यों को करने वाले कर्मचारियों के दो समूहों के बीच भेदभाव किया जाता था। "समान काम के लिए समान वेतन" का सिद्धांत कोई अमूर्त नहीं है, यह राज्य के लिए प्रकृति, कर्तव्यों, जिम्मेदारियों और शैक्षिक योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न संवर्गों के लिए अलग-अलग वेतनमान निर्धारित करने के लिए खुला है। विशेष ग्रेड में प्रवेश के लिए अलग-अलग योग्यताओं के साथ सेवा में निर्धारित विभिन्न ग्रेड। विभिन्न संवर्गों के लिए अलग-अलग वेतनमान निर्धारित करने के लिए सेवा की अवधि के आधार पर उच्च योग्यता और अनुभव वैध विचार हैं। सिद्धांत का अनुप्रयोग तब उत्पन्न होता है जब कर्मचारी हर

मामले में, शैक्षिक योग्यता, कर्तव्यों, कार्यों और जिम्मेदारियों के माप में समान होते हैं और फिर भी उन्हें वेतन में समानता से वंचित किया जाता है। यदि वेतन के विभिन्न मानकों को निर्धारित करने के लिए वर्गीकरण उचित संबंध पर आधारित है तो सिद्धांत लागू नहीं होगा। लेकिन अगर वर्गीकरण अवास्तविक और अनुचित आधार पर स्थापित किया जाता है तो यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करेगा और समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांत का अपना रास्ता होना चाहिए। अपीलार्थियों के विद्वान वकील द्वारा दिए गए निर्णयों में, इस न्यायालय ने इस निष्कर्ष को दर्ज करने के बाद राहत प्रदान की कि पीड़ित कर्मचारियों के साथ संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत समानता खंड का उल्लंघन करते हुए भेदभाव किया गया था, बिना वर्गीकरण के लिए कोई तर्क दिए।

11. इस न्यायालय के कई निर्णयों में समान काम के लिए समान वेतन के दावे को इस आधार पर नकार दिया गया है कि समान या समान काम करने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित विभिन्न वेतनमान जिम्मेदारियों, शैक्षिक योग्यता, अनुभव और अन्य संबद्ध मामलों के माप पर आधारित वर्गीकरण के आधार पर अनुमत हैं। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज स्टेनोग्राफर्स (मान्यता प्राप्त) बनाम भारत संघ में न्यायमूर्ति सब्यसाची मुखर्जी ने कहाः

"विश्वसनीयता और जिम्मेदारी के संबंध में गुणात्मक अंतर हो सकते हैं। कार्य समान हो सकते हैं लेकिन जिम्मेदारियों से फर्क पड़ता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अक्सर अंतर डिग्री

का मामला होता है और उन लोगों द्वारा मूल्य निर्णय का एक तत्व होता है जिन पर वेतन के पैमाने और सेवा की अन्य शर्तों को तय करने में प्रशासन का प्रभार होता है। जब तक इस तरह के मूल्य निर्णय को उचित रूप से एक बोधगम्य मानदंड पर बनाया जाता है, जिसका विभेदन के उद्देश्य के साथ तर्कसंगत संबंध है, इस तरह का विभेदन भेदभाव के बराबर नहीं होगा। इस बात पर जोर देना महत्वपूर्ण है कि समान काम के लिए समान वेतन संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुरूप है। लेकिन यह स्वाभाविक रूप से होता है कि असमान काम के लिए समान वेतन उस अधिकार का निषेध होगा।

विद्वान न्यायाधीश ने आगे कहाः "शारीरिक श्रम की समान मात्रा में काम की अलग-अलग गुणवत्ता हो सकती है, कुछ अधिक संवेदनशील, कुछ को अधिक कौशल की आवश्यकता होती है, कुछ कम-यह रोजगार की प्रकृति और संस्कृति से भिन्न होती है। समान वेतन के बारे में समस्या का हमेशा गणितीय सूत्र में अनुवाद नहीं किया जा सकता है। यदि इसका मांग किए गए उद्देश्य के साथ तर्कसंगत संबंध है, जैसा कि प्रशासनिक अधिकारियों के मूल्य निर्णय की एक निश्चित राशि से पहले दोहराया गया है, जिन पर वेतनमान तय करने का आरोप है, उन्हें उनके पास छोड़ दिया जाना चाहिए और अदालत द्वारा इसमें तब तक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता जब तक कि यह प्रदर्शित नहीं किया जाता है कि यह या तो तर्कहीन है या किसी भी आधार पर आधारित नहीं है या कानून में या वास्तव में दुर्भावनापूर्ण है।

12. उत्तर प्रदेश राज्य बनाम जे. पी. चौरसिया मामले में, इस न्यायालय ने योग्यता, अनुभव और वरिष्ठता के आधार पर उचित वर्गीकरण के आधार पर समान काम के लिए समान वेतन के लिए पीठ सचिवों के दावे को खारिज कर दिया, हालांकि दोनों समूह के कर्मचारी समान कर्तव्यों का पालन कर रहे थे और समान जिम्मेदारियां निभा रहे थे। मेवा राम कनौजिया बनाम एम्स मामले में इस न्यायालय ने याचिकाकर्ता को समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांत को लागू करने पर वेतन में समानता के लिए राहत देने से इनकार कर दिया।

13. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए हमारी राय है कि जहां दो वर्ग के कर्मचारी समान या समान कर्तव्यों का पालन करते हैं और समान शैक्षणिक योग्यता के साथ समान जिम्मेदारी के साथ समान कार्यों को करते हैं, वे समान वेतन के हकदार होंगे। यदि राज्य उन्हें वेतन में समानता से वंचित करता है, तो उसकी कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन होगी, और अदालत भेदभाव को समाप्त कर देगी और पीड़ित कर्मचारियों को राहत प्रदान करेगी। लेकिन इस तरह की राहत देने से पहले अदालत को दो अलग-अलग वेतनमान निर्धारित करने में राज्य की कार्रवाई के पीछे के तर्क पर विचार और विश्लेषण करना चाहिए। यदि संबंधित नियमों, आदेशों, कर्तव्यों की प्रकृति, कार्यों, जिम्मेदारी के माप और संबंधित पदों के लिए आवश्यक शैक्षिक योग्यताओं के विश्लेषण पर, अदालत ने पाया कि दोनों वर्गों के कर्मचारियों को अलग-अलग व्यवहार देने में राज्य द्वारा किया गया वर्गीकरण तर्कसंगत आधार पर किया गया है, जो

प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों के साथ संबंध रखता है, तो वर्गीकरण को बरकरार रखा जाना चाहिए। समान काम के लिए समान वेतन का सिद्धांत समान लोगों के बीच लागू होता है, इसे असमान कर्मचारियों पर लागू नहीं किया जा सकता है। समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांतों को लागू करने की मांग करने वाले पीड़ित व्यक्ति को राहत तभी दी जा सकती है जब अदालत के समक्ष यह प्रदर्शित किया जाए कि राज्य द्वारा दोनों वर्गों के कर्मचारियों के लिए दो अलग-अलग पैमाने निर्धारित करने में बिना किसी उचित वर्गीकरण के भेदभावपूर्ण भेदभाव किया जाता है। यदि पीड़ित कर्मचारी भेदभाव प्रदर्शित करने में विफल रहते हैं, तो समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांत को अदालत द्वारा अमूर्त रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। यह सवाल कि सेवा के एक विशेष वर्ग को कौन सा पैमाना प्रदान किया जाना चाहिए, कार्यपालिका पर छोड़ दिया जाना चाहिए और केवल तभी जब बराबर के बीच भेदभाव किया जाता है, अदालत को गलत को पूर्ववत करने और समान रूप से रखे गए कर्मचारियों के बीच समानता सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए। हालाँकि अदालत अलग-अलग वर्ग के कर्मचारियों के लिए समान वेतनमान निर्धारित नहीं कर सकती है।

(ii) उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम जे. पी. चौरसिया और अन्य (1989) 1 एस. सी. सी. 121 में, यह निम्नानुसार आयोजित किया गया थाः -

"20. पहले तैयार किए गए दूसरे प्रश्न की सावधानीपूर्वक जांच करने की आवश्यकता है। सवाल वर्तमान मामले के लिए विशेष नहीं है। यह

ऐसे सभी मामलों के लिए प्रासंगिक है। यह सामान्य रूप से सिविल सेवाओं को प्रभावित करने वाला मामला है। सवाल यह है कि क्या समान या समान काम या कर्तव्यों का पालन करने वाले व्यक्तियों के एक ही संवर्ग में वेतन के दो पैमाने हो सकते हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सभी न्यायपीठ सचिवों के कर्तव्य निर्विवाद रूप से समान हैं। लेकिन उन्हें अलग-अलग वेतनमान के साथ दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है। बेंच सेक्रेटरी ग्रेड । बेंच सेक्रेटरी ग्रेड ॥ की तुलना में उच्च वेतनमान में हैं। उच्च वेतनमान की पात्रता योग्यता-सह-श्रेष्ठता के आधार पर चयन पर निर्भर करती है। क्या यह कहा जा सकता है कि यह संविधान के तहत गारंटीकृत समानता के अधिकार का उल्लंघन होगा?

31. वर्तमान मामले में, सभी न्यायपीठ सचिव एक ही काम कर सकते हैं, लेकिन उनके काम की गुणवत्ता भिन्न हो सकती है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा बनाए गए नियमों के तहत, बेंच सचिव ग्रेड । का चयन एक चयन समिति द्वारा किया जाता है। चयन वरिष्ठता के संबंध में योग्यता पर आधारित है। उनका चयन बेंच सेक्रेटरी ग्रेड-2 में किया जाता है जब बेंच सेक्रेटरी ग्रेड-॥ अनुभव प्राप्त करते हैं और अधिक योग्यता भी प्रदर्शित करते हैं, तो उन्हें बेंच सेक्रेटरी ग्रेड-1 के रूप में नियुक्त किया जाता है। इस प्रकार नियम उच्च वेतनमान की पात्रता के उद्देश्य से एक उचित वर्गीकरण करते हैं। उच्च न्यायालय ने नियमों के तहत प्रदान किए गए मानदंडों की पूरी तरह से अनदेखी की है। योग्यता उच्च वेतनमान के अनुदान को नियंत्रित करती है और उस योग्यता का मूल्यांकन एक सक्षम

प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा। इसलिए नियमों के तहत किए गए वर्गीकरण को समान काम के लिए समान वेतन के अधिकार का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है।

6. इसके विपरीत, उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील व्यावसायिक कर्मचारी परास्नातक संघ ने प्रस्तुत किया कि व्यावसायिक परास्नातक के रूप में नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यता शुरू से ही तीन साल के अनुभव के साथ एक डिग्री या डिप्लोमा थी क्योंकि दोनों योग्यताओं को बराबर रखा गया था। चयन की प्रक्रिया के साथ-साथ नौकरी की प्रकृति भी समान थी। इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों के बीच ऐसा कोई अंतर या भेद नहीं लाया गया था। विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे कहा कि राज्य सरकार ने उन लोगों के बीच मनमाना अंतर लाने की मांग की है जिन्हें 10+1 और 10 + 2 के समान वर्गों को पढ़ाने के लिए नियुक्त किया गया था और इस तरह की मनमाना कार्रवाई कानून के विपरीत है और उच्च न्यायालय द्वारा ठीक करने का निर्देश दिया गया है। विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे कहा कि समान रूप से स्थित व्यक्तियों के बीच कोई भेदभाव नहीं हो सकता है, चाहे वह सरकारी अधिसूचना के माध्यम से हो या नियमों में किसी संशोधन के माध्यम से। यह दलील कि अनजाने में गलती हुई थी, अभिलेख के विपरीत है और यह कानून में जानबूझकर किया गया भेद है जिसे अपीलार्थियों द्वारा लाया जाना चाहिए। विद्वान वरिष्ठ वकील ने अंततः तर्क दिया कि उच्च न्यायालय विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखने में सही था और वर्तमान अपील खारिज होने योग्य है।

7. व्यावसायिक व्याख्याताओं (प्रतिवादी संख्या 5 और 7) की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील ने कहा कि राज्य सरकार ने संविधान की धारा 309 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंजाब सिविल सेवा (संशोधित वेतन) · (प्रथम संशोधन) नियम, 1998 बनाए। उक्त नियमों के अनुसार, व्यावसायिक व्याख्याताओं और

व्यावसायिक परास्नातकों के लिए वेतन के विभिन्न पैमाने निर्धारित किए गए हैं। सरकार ने दोनों पदों के लिए आवश्यक विभिन्न योग्यताओं सहित विभिन्न कारकों की जांच करने के बाद, व्यावसायिक व्याख्याताओं के लिए व्यावसायिक परास्नातकों की तुलना में उच्च वेतनमान निर्धारित किया है। उक्त विभेदन को उचित रूप से एक बोधगम्य मानदंड पर प्रामाणिक बनाया गया है, जिसका विभेदन के उद्देश्य के साथ एक तर्कसंगत संबंध है। विशेष रूप से, उक्त नियमों पर उच्च न्यायालय के समक्ष व्यावसायिक गुरुओं द्वारा हमला नहीं किया गया था। इस प्रकार, ऐसे वैधानिक नियम हैं जो इस क्षेत्र को धारण करते हैं और दोनों पदों के लिए अलग-अलग वेतनमान उक्त नियमों के आधार पर निर्धारित किए गए हैं। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने उक्त नियमों पर ध्यान दिए बिना, आदेश के माध्यम से, व्यावसायिक परास्नातकों को व्यावसायिक व्याख्याताओं के वेतनमान नहीं देने में सरकार की कार्रवाई को गलती से खारिज कर दिया।

8. विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे कहा कि इस न्यायालय के कई मामलों में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि 'समान काम के लिए समान वेतन' के सिद्धांत का हर मामले में कोई यांत्रिक अनुप्रयोग नहीं है और अनुच्छेद 14 भर्ती किए गए व्यक्तियों के गुणों या विशेषताओं के आधार पर उचित योग्यता की अनुमति देता है। समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत के लाभ का दावा करने के लिए, संबंधित कर्मचारी को यह स्थापित करना होगा कि दोनों पदों की योग्यता, पात्रता, चयन/भर्ती का तरीका, कार्य और कर्तव्यों की प्रकृति और गुणवत्ता और प्रयास, विश्वसनीयता, गोपनीयता, निपुणता, कार्यात्मक आवश्यकता और जिम्मेदारियां और स्थिति समान हैं। इस दावे के समर्थन में, विद्वान वरिष्ठ वकील ने श्याम बाबू वर्मा और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (1994) 2 एस. सी. सी. 521 और डब्ल्यू. बी. सरकार बनाम तरुण के. रॉय और अन्य (2004) 1 एस. सी. सी. 347 में इस न्यायालय के फैसलों की ओर इशारा किया।

9. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने इस बात पर जोर दिया कि वेतन निर्धारण आदि से संबंधित मामले विशेष रूप से सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समितियों के दायरे में आते हैं और अदालत को ऐसी समितियों द्वारा किए गए वेतन निर्धारण के निर्णयों में हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए। जब तक वेतनमान और अन्य सेवा शर्तों आदि को तय करने में प्रशासन का भार संभालने वालों के निर्णय को उचित रूप से एक बोधगम्य मानदंड पर प्रामाणिक बनाया जाता है, जिसका भेदभाव के उद्देश्य के साथ तर्कसंगत संबंध है, तब तक इस तरह का भेदभाव भेदभाव नहीं होगा। यह निर्धारित करना कि दो पद समान हैं या नहीं, विशेषज्ञ समिति का काम है और न्यायालय को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इस निवेदन के समर्थन में, विद्वान वरिष्ठ वकील इस न्यायालय के निम्नलिखित निर्णय की ओर इशारा करते हैं, अर्थात्, इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड बनाम वर्कमेन, इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। (2007) आई एस सी सी 408 और भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बनाम के. पी. सुब्बैया और अन्य (2003) 11 एस सी सी 646।

।0. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने अंततः प्रस्तुत किया कि व्यावसायिक परास्नातकों और व्यावसायिक व्याख्याताओं के बीच पूर्ण पहचान के अभाव में, उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा पारित दिनांकित 16.07.2003 आदेश को रद्द करने में गलती की, जिसके तहत उसने उन व्यावसायिक परास्नातकों को उच्च वेतनमान का लाभ नहीं देने का निर्णय लिया है जिन्होंने 08.07.1995 द्वारा इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर या डिग्री की योग्यता प्राप्त नहीं की थी। सरकार का उक्त निर्णय वैधानिक नियमों के अनुरूप था और इसे उचित रूप से एक बोधगम्य मानदंड पर प्रामाणिक बनाया गया था, जिसका भेदभाव के उद्देश्य के साथ एक तर्कसंगत संबंध है। इसलिए, उच्च न्यायालय ने इसे रद्द करने में गलती की और वह भी इस क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले वैधानिक नियमों पर बहुत कम ध्यान दिए बिना।

चर्चाः

11. यहाँ उत्तरदाता रुपये के वेतनमान का दावा कर रहे हैं। 6, 400-10,640/- 01.01.1996 से प्रभावी होगा जो व्याख्याताओं को दिए गए पैमाने के बराबर होगा। यह उनका दावा है कि जब उन्हें शुरू में तदर्थ आधार पर व्यावसायिक मास्टर के रूप में नियुक्त किया गया था और उन्हें रुपये के वेतनमान में रखा गया था। 300-600- इंजीनियरिंग व्यापार में छात्रों को पढ़ाने के लिए इंजीनियरिंग में एक डिग्री आवश्यक योग्यता थी और गैर-इंजीनियरिंग व्यापार के लिए, एक उम्मीदवार के पास आईटी के साथ बी. ए. की योग्यता होनी आवश्यक थी! डिप्लोमा। ये योग्यताएँ पी. ई. एस. कक्षा III नियमों के तहत व्याख्याताओं के बराबर थीं। यह भी रिकॉर्ड में है कि प्रासंगिक समय में, व्याख्याताओं के पद रुपये के निचले पैमाने पर थे। 250-550-। वोकेशनल मास्टर्स को जो पैमाना दिया गया था, वह उस पैमाने के बराबर था जिसका आनंद हेड मास्टर्स ने लिया था। वर्ष 1978 में, वेतन आयोग ने रुपये के वेतनमान की सिफारिश की। 700-1300-दोनों व्याख्याताओं के साथ-साथ व्यावसायिक परास्नातकों के लिए। इस प्रकार, व्यावसायिक गुरुओं और व्याख्याताओं को एक ही पैमाने पर रखा गया था। वेतन में समानता बाद के वेतन संशोधन में भी जारी रही और दोनों श्रेणियों को रुपये के वेतनमान में रखा गया। 1,800-3,200/-. इस मामले के दृष्टिकोण से, व्याख्याताओं और व्यावसायिक परास्नातकों के कर्तव्यों की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

12. हालाँकि, जब वर्ष 1998 में वेतनमान को 01.01.1996 से संशोधित किया गया था, तो व्याख्याताओं और व्यावसायिक परास्नातकों के वेतनमान के बीच एक असमानता पैदा हो गई थी। जबकि व्याख्याताओं को रुपये का वेतनमान दिया गया था। 6,400-10,640/-, यहाँ व्यावसायिक परास्नातकों को रुपये के परिवर्तित वेतनमान में तय किया गया था। 5, 800-9,200/-। यह भी रिकॉर्ड में है कि वोकेशनल मास्टर्स, जिन्हें पहले 08.07.1995 में नियुक्त किया गया था, ने दावा किया कि उन्हें

व्याख्याताओं से कम वेतनमान नहीं दिया जा सकता है। दिनांक 07.11.2002 की अधिसूचना के माध्यम से, राज्य सरकार ने एक स्पष्टीकरण जारी किया कि 08.07.1995 पर या उसके बाद नियुक्त व्यावसायिक परास्नातकों को न तो शैक्षिक योग्यता के आधार पर व्यावसायिक व्याख्याता के रूप में नामित किया जा सकता है और न ही उन्हें रु। 6,400-10,640/- उन्हें 01.01.1996 के प्रभाव से यह कहते हुए कि उच्च पैमाना उन लोगों के लिए स्वीकार्य होगा जो 08.07.1995 से पहले सेवा में थे। दिनांक 07.11.2002 की अधिसूचना को ध्यान में रखते हुए, उच्च पैमाना व्यावसायिक परास्नातकों को दिया गया था। आई. डी. 1 पर राज्य सरकार ने व्यावसायिक परास्नातकों को पी. ई. एस. कक्षा II में पदोन्नति के लिए विचार करने के लिए 15 प्रतिशत का कोटा प्रदान किया। इस बीच, 16.07.2003 पर, राज्य सरकार ने बाद की अधिसूचना के माध्यम से, 07.11.2002 और 16.05.2003 की पिछली अधिसूचनाओं को हटाते हुए निर्देश दिया कि पदनाम और वेतनमान रु। 01.01.1996 से प्रभावी 6,400-10,640/- केवल उन व्यावसायिक परास्नातकों के लिए स्वीकार्य होंगे जिन्हें 08.07.1995 से पहले नियुक्त किया गया है और जिनके पास 08.07.1995 द्वारा इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर या डिग्री की योग्यता है। उक्त अधिसूचना के आधार पर, राज्य सरकार ने नियमों के तहत उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद व्यावसायिक परास्नातकों को दी गई अतिरिक्त राशि की वसूली के आदेश पारित किए। हालाँकि, सभी व्यावसायिक परास्नातकों को व्यावसायिक व्याख्याताओं के रूप में फिर से नामित करने का उत्तरदाताओं का दावा अभी भी लंबित था।

13. जैसा कि नाम से पता चलता है, व्यावसायिक पाठ्यक्रम वे पाठ्यक्रम हैं जिनमें शिक्षण नियमित रूप से नहीं होता है। व्यावसायिक पाठ्यक्रम विभिन्न क्षेत्रों में छात्रों को तैयार करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह युवाओं को विभिन्न नौकरियों के लिए प्रशिक्षित करता है और उन्हें विशेष कौशल हासिल करने में मदद

करता है। व्यावसायिक शिक्षा को नौकरी उन्मुख शिक्षा भी कहा जा सकता है। यह एक व्यक्ति को तुलनात्मक रूप से कम उम्र में किसी विशेष मामले में कुशल बनने में मदद करता है। वर्तमान मामले में, राज्य सरकार ने वर्ष 1975 में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की आवश्यकता महसूस की और तदनुसार इन पाठ्यक्रमों के विनियमन के लिए उपयुक्त प्रावधान किए। सरकारी आदेशों के अनुसार, शुरू में, बहुत कम विषयों को छोड़कर, "व्यावसायिक परास्नातक" के पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता डिग्री या स्नातकोत्तर थी।

14. यह कानून का एक प्रमुख सिद्धांत है कि सरकार को कानून के शासन का पालन करना होगा और संविधान के मूल्यों और सिद्धांतों को बनाए रखना होगा। यहाँ उत्तरदाताओं ने आरोप लगाया कि एक ही संवर्ग के व्यक्तियों के बीच एक कृत्रिम अंतर पैदा करना अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा यानी कानून के समक्ष समानता और इसलिए, इस तरह के कार्य को बनाए नहीं रखा जा सकता है। समानता का सिद्धांत एक गतिशील और विकसित अवधारणा है जिसके कई आयाम हैं। संविधान के अनुच्छेद (आई. डी. 1), कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण का आश्वासन देने के अलावा, रोजगार के मामलों में भेदभाव को भी अस्वीकार करते हैं, जिसका उद्देश्य समानता प्राप्त करना नहीं है। यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि हालांकि अनुच्छेद 14 वर्ग कानून को मना करता है लेकिन यह उचित वर्गीकरण को मना नहीं करता है। जब वर्गीकरण प्रदान करने वाले सांविधिक प्रावधान के किसी भी नियम पर इस आधार पर हमला किया जाता है कि यह अनुच्छेद 14 के विपरीत है, तो इसकी वैधता को बनाए रखा जा सकता है यदि यह दो परीक्षणों को संतुष्ट करता है, अर्थात्, वर्गीकरण एक बोधगम्य अंतर पर आधारित होना था जो व्यक्तियों या चीजों को समूह से बाहर रखे गए अन्य लोगों से अलग करता है, और विचाराधीन अंतर में नियम या विचाराधीन वैधानिक प्रावधान द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के लिए एक उचित

संबंध होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, वर्गीकरण के आधार और क़ानून या नियम द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के बीच कुछ तर्कसंगत संबंध होना चाहिए।

15. यह स्पष्ट है कि प्रारंभिक नियुक्ति के समय, डिग्री धारकों और डिप्लोमा धारकों दोनों को चयन की एक सामान्य प्रक्रिया द्वारा नियुक्त किया गया था, जहां इंजीनियरिंग व्यापार के लिए एक डिग्री की आवश्यकता थी और गैर-इंजीनियरिंग व्यापार के लिए एक डिप्लोमा को उपयुक्त योग्यता माना जाता था। एक सामान्य विज्ञापन जारी किया गया और चयन की एक सामान्य प्रक्रिया के कारण उन सभी व्यक्तियों की नियुक्ति की गई जिन्हें व्यावसायिक परास्नातक के रूप में नामित किया गया था। उन्हें सामान्य व्याख्याताओं से अधिक वेतनमान पर नियुक्त किया जाता था। उन्होंने वर्ष 1978 तक उच्च स्तर प्राप्त करना जारी रखा जब सामान्य व्याख्याताओं के वेतनमान को व्यावसायिक परास्नातकों के वेतनमान के बराबर लाया गया। वर्ष 1995 में ही राज्य सरकार द्वारा व्यावसायिक व्याख्याताओं के रूप में डिग्री धारकों और व्यावसायिक मास्टर के रूप में डिप्लोमा धारकों के बीच अंतर पैदा करने का प्रयास किया गया था।

16. इसके अलावा, शुरुआत से ही, व्यावसायिक परास्नातक के रूप में नियुक्ति के लिए शैक्षिक योग्यता तीन साल के अनुभव के साथ एक डिग्री या डिप्लोमा थी क्योंकि दोनों योग्यताओं को बराबर रखा गया था। सभी व्यक्तियों को चयन की एक सामान्य प्रक्रिया द्वारा नियुक्त किया गया था और वे एक ही काम करते हुए एक ही वर्ग को पढ़ाते हैं। इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों के बीच कोई भेद नहीं किया जा सकता है। बाद में अपीलकर्ताओं ने कुछ व्यावसायिक परास्नातकों को व्यावसायिक व्याख्याताओं के रूप में नामित किया और दोनों के बीच एक कृत्रिम अंतर लाया। डिग्री धारकों और स्नातकोत्तरों को व्यावसायिक व्याख्याता के रूप में फिर से नामित करने के कारण भी, कथित अधिसूचना से पहले डिग्री धारकों और डिप्लोमा धारकों की जिम्मेदारियों और

वित्तीय मामलों में कोई बदलाव नहीं हुआ था, जो तथ्य राज्य द्वारा विधिवत स्वीकार किए जाते हैं। व्यावसायिक व्याख्याताओं और व्यावसायिक गुरुओं के बीच कोई अंतर नहीं है और वे एक एकीकृत संवर्ग और वर्ग बनाते हैं। समान रूप से स्थित व्यक्तियों के बीच कोई भेदभाव नहीं हो सकता है, चाहे वह सरकारी अधिसूचना के माध्यम से हो या नियमों में किसी संशोधन के माध्यम से। जहां तक काम की प्रकृति का संबंध है, यह कहा गया है कि व्यावसायिक मास्टर इंजीनियरिंग/गैर-इंजीनियरिंग ट्रेडों में वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं और उनके पास तकनीकी योग्यता है जबकि व्यावसायिक व्याख्याता भी उन्हीं स्कूलों में समान कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। व्यावसायिक मास्टर और व्याख्याता दोनों एक ही कक्षाओं को पढ़ा रहे हैं, यानी 10+1 और 10+2 और इसलिए काम, जिम्मेदारियों और कर्तव्यों की प्रकृति समान है और वार्डों में वेतनमान भी 1978 से समान रखा गया था।

17. समानता का सिद्धांत, राज्य द्वारा किसी भी नीति के निर्माण में भी मौलिक है और इसकी झलक भारत के संविधान के भाग IV में सन्निहित अनुच्छेद 38,39,39ए, 43 और 46 में पाई जा सकती है। भारत के संविधान के इन अनुच्छेदों में यह अधिदेश दिया गया है कि राज्य एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए संवैधानिक दायित्व के अधीन है जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करे, अन्य बातों के साथ-साथ, मौद्रिक असमानताओं को कम करे, और आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार सुनिश्चित करे और पर्याप्त मजदूरी प्रदान करे ताकि जीवन का एक उचित स्तर सुनिश्चित किया जा सके और कमजोर वर्गों के आर्थिक हितों को बढ़ावा दिया जा सके। अर्थात्, यदि राज्य एक वर्ग को कुछ आर्थिक लाभ दे रहा है, जबकि दूसरे को इससे वंचित कर रहा है, तो इसे उचित ठहराने की जिम्मेदारी राज्य पर है, विशेष रूप से उन परिस्थितियों में जब दोनों वर्गों या व्यक्तियों के समूह के साथ राज्य द्वारा अतीत में समान व्यवहार किया गया था। चूँकि

व्यावसायिक परास्नातक 41 वेतन आयोग के आवेदन से पहले व्यावसायिक व्याख्याताओं के समान वेतन प्राप्त कर रहे थे, इसलिए उनके वेतन और भत्तों में कटौती करने का कोई भी प्रयास मनमानेपन के बराबर होगा जिसे कानून की नजर में बनाए नहीं रखा जा सकता है यदि इसके लिए कोई उचित औचित्य नहीं दिया जाता है।

18. हम इस तथ्य से अवगत हैं कि शैक्षिक योग्यता और कर्तव्यों की प्रकृति के आधार पर एक अंतर पैमाने की अनुमति है। हालाँकि, हमारे लिए यह समान रूप से स्पष्ट है कि यदि दो श्रेणियों के कर्मचारियों को शुरू में समान माना जाता है, तो उनके साथ ऐसा व्यवहार जारी रहना चाहिए. जब तक कि कुछ ठोस कारणों से एक अलग व्यवहार उचित न हो। ऐसे मामले में जहां कर्तव्यों की प्रकृति में भारी बदलाव किया जाता है, वेतन के अंतर पैमाने को उचित ठहराया जा सकता है। इसी तरह, यदि किसी विशेष पद के लिए उच्च योग्यता निर्धारित की जाती है, तो उच्च वेतनमान दिया जा सकता है। हालाँकि, यदि बुनियादी योग्यताएँ और नौकरी की आवश्यकताएँ वही बनी रहती हैं जो वे शुरू में निर्धारित की गई थीं, तो न्यायालय अंतर व्यवहार के अनुसार प्राधिकरण की कार्रवाई को स्वीकार करने में अनिच्छुक होगा जब तक कि कुछ अच्छे कारणों का खुलासा नहीं किया जाता है। इस प्रकार, विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा जिन निर्णयों पर भरोसा किया गया है, वे स्पष्ट रूप से अलग हैं और वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होते हैं।

निष्कर्षः

19. चल रही चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हमारी यह सुविचारित राय है कि उच्च न्यायालय यह घोषणा करने में पूरी तरह से उचित था कि व्यावसायिक स्वामी रुपये के वेतनमान के हकदार हैं। 6,400-10,640/- इस आधार पर कि व्यावसायिक शिक्षकों द्वारा निर्वहन किए जाने वाले कर्तव्यों की प्रकृति व्यावसायिक व्याख्याताओं के

समान है और दोनों के बीच वर्गीकरण करने के पीछे कोई तर्क नहीं था, विशेष रूप से जब दोनों श्रेणियों को वार्डों पर 1978 से सभी पिछले वेतन संशोधनों में एक और समान माना गया था। उनके कर्तव्यों और वेतनमान की प्रकृति को बदलने के लिए दिनांकित अधिसूचना 31.03.1995 देखें। इसके अलावा, दिनांकित 16.07.2003 का विवादित आदेश इस आधार पर रद्द किया जाना चाहिए कि इसे प्राकृतिक न्याय के नियमों का पालन किए बिना पारित किया गया है। संबंधित कर्मचारियों को सुनवाई का अवसर दिए बिना इसे पारित नहीं किया जा सकता था।

20. यह अब अच्छी तरह से तय हो गया है कि प्राकृतिक न्याय के नियमों का पालन किए बिना नागरिक परिणामों का कारण बनने वाला कोई भी आदेश पारित नहीं किया जा सकता है, जैसा कि भगवान शुक्ला बनाम भारत संघ और अन्य में किया गया था। ए. आई. आर. 1994 एस. सी. 2480 जिसमें यह निम्नलिखित रूप में आयोजित किया गया था।

> "3. हमने पक्षों के लिए विद्वान वकील को सुना है। यह विवादित नहीं है कि याचिकाकर्ता का मूल वेतन 1970 से 190 रुपये निर्धारित किया गया था। इस बात पर भी कोई विवाद नहीं है कि अपीलार्थी का मूल वेतन घटाकर एक लाख रुपये कर दिया गया था। 181 बजे से रु। 1991 में 190 पैन पूर्वव्यापी रूप से डब्ल्यू. ई. एफ. 1812.1970.The अपीलार्थी से स्पष्ट रूप से नागरिक परिणामों के साथ मुलाकात की गई है, लेकिन उसे अपने मूल वेतन में कमी के खिलाफ कारण दिखाने का कोई अवसर नहीं दिया गया था। विभाग द्वारा उनका वेतन कम करने से पहले उन्हें नोटिस भी नहीं दिया गया था और कानून द्वारा ज्ञात किसी भी प्रक्रिया का पालन किए बिना उनकी पीठ पीछे आदेश दिया गया था। इस प्रकार, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का घोर

उल्लंघन हुआ है और अपीलार्थी को बिना सुने भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा है। कार्रवाई में निष्पक्षता इस बात की गारंटी देती है कि ऐसा कोई भी आदेश जो किसी कर्मचारी को नागरिक परिणामों से पीड़ित करता है, संबंधित को नोटिस दिए बिना और मामले में उसे सुनवाई दिए बिना पारित नहीं किया जाना चाहिए। चूंकि ऐसा नहीं किया गया था, इसलिए न्यायाधिकरण के समक्ष आक्षेपित दिनांकित आदेश (ज्ञापन) को निश्चित रूप से कायम नहीं रखा जा सका और केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण अपीलार्थी की याचिका को खारिज करने में त्रुटि में पड़ गया। ट्रिब्यूनल के आदेश को अलग रखा जाना चाहिए। हम, तदनुसार, इस अपील को स्वीकार करते हैं और केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के दिनांकित 17.9,1993 के आदेश के साथ-साथ न्यायाधिकरण के समक्ष दिनांकित 25.7.1991 के आदेश (ज्ञापन) को खारिज कर देते हैं, जिसमें अपीलार्थी के मूल वेतन को रु। 190 से रु। 181 डब्ल्यू. ई. एफ 18.12,1970।"

21. 16.07.2003 दिनांकित आदेश कानून द्वारा ज्ञात किसी भी प्रक्रिया का पालन किए बिना व्यावसायिक गुरुओं की पीठ के पीछे किया गया था। इस प्रकार प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का घोर उल्लंघन हुआ है और उत्तरदाताओं को बिना सुने भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा है। कार्रवाई में निष्पक्षता इस बात की गारंटी देती है कि ऐसा कोई भी आदेश जो किसी कर्मचारी को नागरिक परिणामों से पीड़ित करता है, संबंधित को नोटिस दिए बिना और मामले में उसे सुनवाई दिए बिना पारित नहीं किया जाना चाहिए।

22. हमारे सुविचारित विचार में, उच्च न्यायालय ने गुण-दोष के आधार पर मामले पर विचार करते हुए, दिनांकित 16.07.2003 पत्र को सही ढंग से रद्द कर दिया

है और राज्य सरकार को सभी व्यावसायिक परास्नातकों को दिनांकित 31.03.1995 की अधिसूचना का लाभ देने का निर्देश दिया है

23. उपरोक्त चर्चा को देखते हुए, हम उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं। तदनुसार, अपील को बिना किसी आदेश के खारिज कर दिया जाता है।

याचिका खारिज कर दी गई।

कल्पना के. त्रिपाठी

Disclaimer:- यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक **मनीष शर्मा** द्वारा किया गया है ।

अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है,एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।